2,500 नए पाठ्यक्रम आरंभ किए जाएंगे, जो आइटी, आटोमोटिव, इलेक्ट्रानिक्स, कृषि, लाजिस्टिक्स एवं पर्यटन जैसे क्षेत्रों की उभरती हुई जरूरतों पर केंद्रित होंगे, प्रधानमंत्री कौशल संवर्धन एवं तकनीकी उन्नयन योजना (पीएम-सेतु) के तहत।

पीएम सेतु योजना

कौशल से आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम

नई दिल्ली में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में उन्नत आइटीआइ के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन (पीएम-सेतु) योजना का शुभारंभ किया। 60 हजार करोड़ रुपये की यह महत्वाकांक्षी पहल आइटीआइ को पारंपरिक प्रशिक्षण केंद्रों से आगे बढ़ाकर उद्योग-केंद्रित उत्कृष्टता संस्थान के रूप में विकसित करने का प्रयास है। यदि इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो यह लाखों युवाओं को कौशल, रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर प्रदान कर भारत के समावेशी विकास की दिशा में नया अध्याय जोड़ सकती है

प्रतीकात्मक

रोहित प्रियदर्शी
लोक नीति विश्लेषक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चार अक्टूबर को प्रधानमंत्री कौशल संवर्धन एवं तकनीकी उन्नयन योजना (पीएम-सेतु) की शुरुआत की है। 60 हजार करोड़ रुपये की यह पहल उस 'विकसित भारत 2047' की परिकल्पना से जुड़ी है, जो देश को आर्थिक, बौद्धिक और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने की आकांक्षा रखती है। यह योजना उस सोच का विस्तार है कि भारत का भविष्य उसकी युवा आबादी के कौशल और सृजनशीलता में निहित है। यह पहल हमें यह सोचने पर विवश करती है कि 21वीं सदी के भारत में विकास का अर्थ केवल आंकड़ों में वृद्धि नहीं, बल्कि ऐसे नागरिकों का निर्माण है जो अपनी योग्यता से विश्व में पहचान बनाएं।

भारत की सबसे बड़ी शक्ति इसका युवा जनसंख्या समूह है, जिसे यदि सही दिशा, प्रशिक्षण और अवसर मिले तो यह जनसंख्या ही जनशक्ति में रूपांतरित हो सकती है। पीएम सेतु इसी परिवर्तन की आधारशिला है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) को आधुनिक, प्रेरणादायक और उद्योगोन्मुख बनाना है, ताकि शिक्षा और रोजगार के बीच की दूरी समाप्त की जा सके। योजना के तहत एक हजार सरकारी आइटीआइ को नया स्वरूप दिया जाएगा, जिसमें 200 को 'हब' और 800 को 'स्पोक' माडल के रूप में विकसित किया जाएगा। हब आइटीआइ उन्नत प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे, जबकि स्पोक आइटीआइ सहयोगी भूमिका निभाते हुए कौशल के प्रसार को अधिक व्यापक बनाएंगे। यह माडल उद्योगों के साथ साझेदारी को सशक्त करेगा और प्रशिक्षण को अधिक व्यावहारिक बनाएगा।

युवाओं को तकनीकी दक्षता : इस योजना के अंतर्गत लगभग 2,500 नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे, जो आइटी, आटोमोटिव, इलेक्ट्रानिक्स, कृषि, लाजिस्टिक्स और पर्यटन जैसे क्षेत्रों की उभरती हुई आवश्यकताओं पर केंद्रित होंगे। पुराने पाठ्यक्रमों को भी आधुनिक औद्योगिक मांगों के अनुरूप अद्यतन किया जाएगा। यह न केवल युवाओं को तकनीकी दक्षता प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें ऐसे कौशल से भी संपन्न करेगा, जिनकी वैश्विक स्तर पर मांग है। इस प्रकार यह योजना युवाओं को 'नौकरी खोजने वाला' नहीं, बल्कि 'नौकरी देने वाला' बनने की दिशा में प्रेरित करती है।

व्यवस्थित प्रयास : केंद्र सरकार ने पांच राष्ट्रीय स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भी सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है, जो देशभर में 12 प्रमुख क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। यह कदम कौशल विकास के प्रयासों को एकीकृत और व्यवस्थित बनाएगा। दरअसल, भारत में लंबे समय से शिक्षा, उद्योग और रोजगार के बीच एक 'स्किल गैप' विद्यमान रहा है। पीएम सेतु इस अंतर को पाटने वाला सेतु बन सकता है, एक ऐसा सेतु जो शिक्षा से रोजगार तक का मार्ग सरल, व्यावहारिक और उत्पादक बनाएगा।

रोजगार सृजन के क्षेत्र में इस योजना की संभावनाएं अत्यंत व्यापक हैं। अनुमान है कि इससे 3.5 करोड़ नई नौकरियां निजी क्षेत्र में उत्पन्न होंगी। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में वास्तविक अवसर प्रदान करेगी। यह केवल रोजगार का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक गरिमा, आर्थिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय आत्मविश्वास का प्रश्न भी है। यह सर्वविदित है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा, जब हर हाथ में कौशल और हर मन में आत्मविश्वास होगा। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों के साथ पीएम सेतु का तालमेल इसे और भी प्रभावी बनाता है। डिजिटल लर्निंग, ई-मैनेजमेंट सिस्टम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रशिक्षण पद्धतियां इस योजना को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बनाएंगी। यह न केवल युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त करेगा, बल्कि भारत को वैश्विक कौशल आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।

प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों की समझ : कौशल विकास अब केवल रोजगार पाने का साधन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का माध्यम भी बन चुका है। पीएम सेतु इस विचार को व्यवहार में उतारने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह योजना केवल संस्थानों का आधुनिकीकरण नहीं करती, बल्कि भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं को दिशा और समाज को विकास की नई ऊर्जा प्रदान करती है। अब प्रशिक्षण केवल कक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उद्योगों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप होगा। यह परिवर्तन उस खाई को पाटने की कोशिश है, जो लंबे समय से शिक्षण संस्थानों और रोजगार बाजार के बीच बनी हुई थी। जब विद्यार्थी अपने प्रशिक्षण के दौरान ही उद्योगों की कार्यप्रणाली, तकनीकी मानकों और प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों को समझेंगे, तब उनकी रोजगार योग्यता स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी।

दक्षता ही पूंजी : प्रधानमंत्री कौशल एवं रोजगार परिवर्तन योजना भारत के कौशल परिदृश्य में एक ऐसा प्रयोग है, जो न केवल रोजगार योग्यता बढ़ाने की दृष्टि से, बल्कि आर्थिक और सामाजिक संरचना को सशक्त बनाने के संदर्भ में भी गहरा महत्व रखता है। यदि हम इसे गहराई से देखें, तो यह पहल केवल आइटीआइ के भौतिक ढांचे को आधुनिक बनाने का प्रयास नहीं है, बल्कि कौशल विकास की उस संपूर्ण प्रक्रिया को पुनर्परिभाषित करने की कोशिश है, जिसमें शिक्षा, उद्योग, प्रौद्योगिकी और स्थानीय आवश्यकताएं एक दूसरे से जुड़ती हैं। यह योजना उस सोच को मूर्त रूप देती है कि अब केवल डिग्री नहीं, बल्कि दक्षता ही भविष्य की वास्तविक पूंजी है। विकसित भारत का मार्ग केवल पूंजी या संसाधनों से नहीं, बल्कि प्रशिक्षित, तकनीकी रूप से दक्ष और नवाचार से परिपूर्ण मानव संसाधन से प्रशस्त होगा। पीएम सेतु उसी भारत के निर्माण की नींव है, जहां हर युवा अपने कौशल से राष्ट्र निर्माण में सहभागी बने, जहां शिक्षा और उद्योग के बीच की खाई मिट जाए, और जहां कौशल ही 'सेतु' बनकर भारत को आत्मनिर्भरता के शिखर तक पहुंचाए। यही इस योजना का सार है, यही भविष्य का भारत है।

योजना के समक्ष संभावित चुनौतियां

प्रधानमंत्री कौशल संवर्धन एवं तकनीकी उन्नयन योजना अपने दृष्टिकोण में अत्यंत दूरदर्शी और परिवर्तनकारी है। फिर भी इसके क्रियान्वयन में कुछ गंभीर चुनौतियां हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में नीति का उद्देश्य जितना श्रेष्ठ होता है, उसके निष्पादन की जटिलता भी उतनी ही बड़ी होती है। सबसे पहली और प्रमुख चुनौती उद्योगों की सक्रिय भागीदारी से जुड़ी है। इस योजना का ढांचा जिस विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) माडल पर आधारित है, उसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी निर्णायक है। लेकिन कई उद्योग लाभप्रदता और दीर्घकालिक निवेश की अनिश्चितता के कारण अभी भी झिझक दिखा रहे हैं। उद्योगों के पास अक्सर तात्कालिक मुनाफे की दृष्टि होती है, जबकि प्रशिक्षण और कौशल विकास दीर्घकालिक निवेश की मांग करता है। यदि उद्योग जगत ने अपेक्षित जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो यह योजना केवल सरकारी प्रबंधन की सीमाओं में सिमटकर रह जाएगी और प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

दूसरी बड़ी चुनौती शिक्षकों की उपलब्धता और गुणवत्ता से जुड़ी है। एक अनुमान के अनुसार, वर्तमान में आइटीआइ संस्थानों में शिक्षकों के लगभग 20 से 30 प्रतिशत पद रिक्त हैं। यह स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हम देखते हैं कि नई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में प्रशिक्षित शिक्षकों की भारी कमी है। यद्यपि योजना में 1,200 व्यावसायिक शिक्षकों को उद्योग-प्रासंगिक प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है, परंतु जब तक वर्तमान रिक्तियां नहीं भरी जातीं और शिक्षण संस्थानों में नियमित प्रशिक्षण संस्कृति विकसित नहीं होती, तब तक यह लक्ष्य अधूरा रहेगा। शिक्षक किसी भी प्रशिक्षण प्रणाली की आत्मा होते हैं, और यदि वही अनुपस्थित हों, तो आत्मा रहित ढांचा अधिक समय तक टिक नहीं सकता।

तीसरी चुनौती ग्रामीण और हाशिए वाले क्षेत्रों में पहुंच से संबंधित है। योजना में हब-एंड-स्पोक माडल के तहत 800 स्पोक आइटीआइ ग्रामीण युवाओं तक कौशल प्रशिक्षण पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की वास्तविक स्थिति चिंताजनक है। जहां बिजली और इंटरनेट की उपलब्धता तक अनियमित हो, वहां डिजिटल लर्निंग की कल्पना व्यावहारिक कठिनाइयों से भरी है। परिवहन और कनेक्टिविटी की कमी से इन संस्थानों तक छात्रों का नियमित पहुंचना ही कठिन हो जाता है। इससे समावेशी विकास की भावना पर आंच आती है, क्योंकि योजना का एक बड़ा लक्ष्य सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाना है। चौथी चुनौती पाठ्यक्रमों की प्रासंगिकता और बाजार की मांग के बीच सामंजस्य की है। ढाई हजार नए कोर्स शुरू करने की घोषणा उत्साहजनक है, परंतु औद्योगिक और तकनीकी दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि पाठ्यक्रम जल्द ही अप्रासंगिक हो सकते हैं।।

अंततः सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय और प्रशासनिक समन्वय की है। 60 हजार करोड़ रुपये के इस विशाल बजट में केंद्र, राज्य और उद्योगों का साझा निवेश होना है। लेकिन राज्यों की प्रशासनिक तैयारियां, वित्तीय पारदर्शिता और केंद्र-राज्य समन्वय की परिपक्वता अभी भी समान स्तर पर नहीं है। इसके अतिरिक्त, यदि वैश्विक वित्तीय संस्थान जैसे विश्व बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक इस परियोजना से जुड़ते हैं, तो उनकी फंडिंग की शर्तें और प्रक्रियाएं कार्यान्वयन में देरी का कारण बन सकती हैं। विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों में यह देरी युवाओं के बीच निराशा भी पैदा कर सकती है। (रोहित प्रियदर्शी)

खरी-खरी

सपनों की जली हुई राख

डा. सुरेश कुमार मिश्रा

एक गांव था। वहां खेत हरे-भरे लहलहाते थे। वहां का युवा किसान रघु हमेशा कहता है कि 'यह जमीन हमारी मां है, इसे बेचना मौत बेचना है'। वह गांववालों को जोड़ता, कारपोरेट लूट के खिलाफ आवाज उठाता। उसका यह मानना है कि धरती को किसी हाल में दूसरे के हाथों में नहीं सौंपना चाहिए। लेकिन एक ठंडी सुबह, जब कोहरा घना था, पुलिस की जीप आई और रघु को उठाकर ले गई। पुलिस ने चार्जशीट में लिखा 'कृषि कानूनों का उल्लंघन कर अराजकता फैलाना'।

अब रघु उस जेल में कैद है जहां खिड़कियां भी बंद हैं। बाहर उसके खेत बंजर हो रहे हैं, फसलें मुरझा रही हैं, जबकि बड़े व्यापारी सौदे कर रहे हैं, जो अन्नदाता है वही अब भूखा मर रहा है। जिस प्रकार से कोई बीज जो कभी फूट न सका, रघु की रातें अब दुःस्वप्नों से भरी हैं। वह याद करता है अपनी पत्नी की मुस्कान, बच्चों की हंसी, लेकिन अब वे आवाजें दूर की गूंज बन गई हैं। रघु की पत्नी रोजाना थाने जाती है। रोज वह थानेदार से पूछती है कि 'कब छूटेगा उसका पति?' लेकिन जवाब मिलता है कि 'उसके मामले की जांच चल रही है'।

सिस्टम की यह जलती हुई क्रूरता ऐसी है कि सपनों को राख में बदल देती है। धीमी आग पर तपाकर, रघु की आंखों में अब वह चमक नहीं, बस एक थकी हुई उदासी है। वह सोचता है कि शायद कल बेहतर होगा, लेकिन दिन गुजरते जाते हैं, शरीर कमजोर होता जाता है, और एक शाम जब सूरज लाल होकर डूबता है, रघु की धड़कन रुक जाती है। उस आखिरी क्षण जहां वह बुदबुदाता है 'मां...', वह करुण बुदबुदाहट पूरे गांव की राख बन जाती है। एक ऐसी पीड़ा जो हड्डियां चटकाती हुई महसूस होती है, लेकिन उस मौत में दबी है एक अनंत करुणा जो खेतों को सींचती है आंसुओं से।

रघु की मौत के बाद गांव शांत हो जाता है। उसकी पत्नी की आंखें पथराई रहती हैं, और कारपोरेट ट्रैक्टर चलते रहते हैं, लेकिन वह राख, वह जली हुई याद कभी नहीं उड़ती, बस बैठ जाती है सीने पर, एक दर्द जो जलता रहता है।

पोस्ट

अगर विश्व कप में स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर के बल्ले से रन नहीं निकलते तो भारत के लिए खिताबी जीत का सफर मुश्किल होता जाएगा ।
बोरिया मजूमदार@BoriaMajumdar

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए और नए जोड़े गए लोगों का विवरण मांगा है। यह ब्योरा तो आयोग को स्वयं सार्वजनिक कर देना चाहिए था। आरके विज@ipsvijrk

जोहो का स्वदेशी एप अरट्टई गूगल प्लेस्टोर और एपल एप स्टोर पर शीर्ष पर पहुंच गया है। करीब एक करोड़ डाउनलोड। हालांकि भारत में वाट्सएप का विकल्प बनने के लिए अभी लंबा सफर तय करना है, पर यह शुरुआत बहुत बढ़िया है।
मिन्हाज मर्चेंट@MinhazMerchant

वैसे तो नेता सत्ता पाने के लिए बड़े-बड़े वादे करते हैं, पर तेजस्वी यादव ने सबको पीछे छोड़ दिया। नीतीश सरकार ने एक करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये डाल दिए तो उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। उसी का नतीजा है कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं।
हर्ष वर्धन त्रिपाठी@MediaHarshVT

जागरण जनमत कल का परिणाम

ब्रिटिश पीएम स्टार्मर का भारत दौरा देश की आर्थिकी में वैश्विक भरोसे को दर्शाता है?

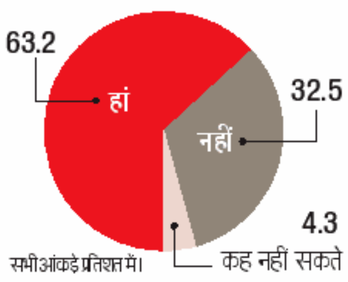

आज का सवाल
बिहार में हर घर से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का तेजस्वी का वादा विश्वसनीय है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

बंदर को दे उस्तरा ट्रंप बढ़ाएं रार,
भारत संग स्टार्मर बढ़ा रहे व्यापार।
बढ़ा रहे व्यापार स्वयं भारत में आकर,
ट्रंप कर रहे लंच साथ गुंडे बैठाकर!
पा मुनीर का साथ ट्रंप बन रहे सिकंदर,
दुनिया आगे जाय आप बस पालो बंदर!!
- ओमप्रकाश तिवारी

शशि शेखर
संपादकीय प्रभारी, रांची

झारखंड डायरी

तूल पकड़ता कुड़मी बनाम आदिवासी मुद्दा

झारखंड में कुड़मी बनाम आदिवासी का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। राज्य एक नई समस्या की राह पर है। हालांकि यह समस्या पुरानी है, लेकिन इस बार यह और बढ़ा हुआ लग रहा है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने के लिए कुड़मी-कुरमी (महतो) लंबे समय से संघर्षरत हैं। इसी 20 सितंबर को रेल टेका आंदोलन के जरिए रेल रोककर इन्होंने राज्यभर में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। खास यह कि इस बार इनके आंदोलन को आजसू पार्टी और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का समर्थन मिल गया। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और जेएलकेएम के विधायक जयमराम महतो स्वयं सड़क पर उतरे और आंदोलन को धार दिया। इससे कुड़मी समुदाय का मनोबल बढ़ा है।

दरअसल कुड़मी स्वयं को आदिवासी घोषित करने की मांग कर रहे हैं और यहां का आदिवासी समुदाय इन्हें आदिवासी मानने को तैयार नहीं है। कुड़मी समुदाय का दावा है कि पहले वे आदिवासी थे। बाद में सरकार ने इस सूची से बाहर कर दिया। परंतु समस्या इतनी आसान नहीं है। दोनों समुदाय अपने-अपने तर्क दे रहे हैं। पुरानी किताबों को खंगाला जा रहा है। ऐतिहासिक दस्तावेज, गजेटियर आदि प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

दोनों ही समुदाय सड़क से लेकर इंटरनेट मीडिया पर भी लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं, आदिवासी भी सड़क पर उतरकर अपनी चट्टानी एकता का परिचय दे रहे हैं। बोकारो में कुड़मी की मांग के विरोध में आदिवासी बचाओ मोर्चा ने विशाल आक्रोश रैली निकाली। आदिवासियों द्वारा रांची और अन्य जिलों में भी रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।

जमशेदपुर में गुरुवार को कुड़मी संगठनों की मांग के विरोध में डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते आदिवासी समुदाय के लोग। जागरण

शोधकर्ता एवं लेखक ग्लैडसन डुंगडुंग कहते हैं कि झारखंड, ओडिशा एवं बंगाल में बसी कुड़मी जाति महाराष्ट्र की कुनबी जाति की उपजाति है। इन लोगों ने कृषि कार्य को अपना मूल "पेशा" बनाने के बाद स्वयं को अपनी मूल जाति "कुर्मी" से अलग कर लिया। इन लोगों ने सबसे पहले मुगलों के अत्याचार से बचने के लिए यहां पहुंचकर संतालों के घरों में शरण ली, इसलिए "माझी महतो भाई-भाई" कहा गया। आज ये स्वयं को आदिवासी घोषित करने के लिए नैरेटिव बना रहे हैं कि "राढ़ सभ्यता" उनका है, उनके पूर्वज 65 हजार साल पहले छोटानागपुर आए थे, अंग्रेजों ने उन्हें आदिवासी माना था, आदि आदि। उनका कहना है कि ब्रिटिश हुकूमत ने इन्हें किसी दस्तावेज में "आदिवासी" का दर्जा नहीं दिया। आदिवासी एक्टिविस्ट एवं कलाकार दिलेश्वर लोहरा कहते हैं कि कुरमी जाति के लोग अनुसूचित जनजाति बनने के लिए फर्जी दस्तावेज का उपयोग कर रहे हैं। झारखंड अलग होने के बाद से ये लोग नया शब्द कुड़मी के साथ आदिवासी पहचान स्थापित करने के लिए आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं।

वहीं दूसरी ओर कुड़मी भी आंदोलन को लेकर कमर कस चुके हैं। राज्य में वृहद झारखंड कुड़मी समिति बन गई है। इसके संयोजक शीतल ओहदार कहते हैं हर जिले में समिति की बैठक होगी। नवंबर-दिसंबर में आठ जिलों में आंदोलन किया जाएगा और अगले साल जनवरी 2026 में मोरहाबादी मैदान में रैली की जाएगी और मार्च में आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। शीतल का दावा है कि उनकी लड़ाई नई नहीं है। वर्ष 1950 के बाद से कुड़मी समुदाय अपने संवैधानिक अधिकार और पहचान के लिए अनवरत संघर्ष कर रहा है। कुड़मी के एसटी दर्जे की मांग का विरोध वे लोग कर रहे हैं जो रूढ़ि परंपरा से दूर हो चुके हैं। हालांकि कुड़मी समुदाय अपनी मांग को लेकर रह-रहकर आंदोलन करता आ रहा है। अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए किताब भी लिख रहा है।

झारखंड की आबादी और यहां की राजनीति में कुड़मी एक प्रमुख घटक है। ये प्रभावशाली भी हैं और खेत से भी मजबूत। राज्य में जितनी आबादी आदिवासियों की है, लगभग उतनी ही इनकी भी है। सरकार क्या करती है, उसका रुख क्या होता है, यह देखना अभी शेष है। मणिपुर की घटना याद होगी। वहां भी यही मांग है जो दो समुदाय एक दूसरे के आमने-सामने आ गए हैं। केंद्र और राज्य दोनों के लिए यह परेशानी का सबब है। अच्छा हो, इसका समाधान जितना शीघ्र हो, राज्य को लाभ होगा। क्योंकि आंदोलन से राज्य का विकास ही प्रभावित होगा।

मंथन

धरोहरों के संरक्षण की चिंता

देश के संग्रहालयों में धरोहरों का संरक्षण किया गया है। ऐसे कई संग्रहालयों की स्थापना व्यक्तिगत प्रयासों से की गई, जिनके संचालन के लिए आर्थिक मदद की व्यवस्था होनी चाहिए

अशोक कुमार
वीसी, हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी

कौशल किशोर
सामाजिक मामलों के जानकार

संग्रहालयों और राष्ट्रीय धरोहरों के बेहतर प्रबंधन एवं संरक्षण का मामला लंबे समय से चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में चिंताजनक यह भी है कि इन धरोहरों की पैरवी करती नीति आयोग की रिपोर्ट पिछले तीन वर्षों से धूल फांक रही है। हरियाणा में झज्जर संग्रहालय और उत्तर प्रदेश के चंदौसी में स्थित पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्रा म्यूजियम की दुर्दशा से यह जाहिर भी होता है। वस्तुतः समूचे विश्व में सबसे पुरानी नागरिक सभ्यताओं में प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता विश्व के पुरातत्वविदों, भाषाविदों और इतिहासकारों को निरंतर आकर्षित करती रही है। लंबे अरसे से इनके मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों पर अंकित लिपि और चिह्न एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। 21वीं सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन से इसे समझने की संभावना नये सिरे से दुनिया भर का ध्यान आकर्षित करने लगी है। हालांकि कांस्य युगीन इस सभ्यता के खंडहर व अवशेष अधिकांशतः उत्तरी भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिले हैं। लेकिन हाल ही में दक्षिण भारत में इससे जुड़े क्रिप्टोग्राफिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने में सक्रियता प्रतीत होती है।

इस खोज में एक नाम उभर कर सामने आता है क्रिप्टोग्राफर भरत राव का, जिन्हें यजनदेवम के नाम से भी जाना जाता है। इस लिपि को समझने के उनके निरंतर प्रयासों से संकेत मिलता है कि शीघ्र ही बड़ी सफलता के करीब हैं। यदि ऐसा हुआ तो यह भारतीय इतिहास की हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल देने वाली साबित होगी। विशेष रूप से चर्चित आर्य आक्रमण सिद्धांत का खंडन करने में इसकी अहम भूमिका होगी। उनके शोध के अनुसार, सिंधु लिपि वास्तव में ब्राह्मी लिपि की प्रारंभिक अथवा पूर्ववर्ती अवस्था हो सकती है, जिसका प्रयोग संस्कृत भाषा लिपिबद्ध करने के लिए किया गया। हालांकि आज बौद्धिक उत्साह के बीच एक दुखद विडंबना भी छिपी है। सिंधु घाटी अनुसंधान में वैश्विक रुचि जहां बढ़ रही है, वहीं इन रहस्यों को उजागर करने वाली वास्तविक कलाकृतियां उपेक्षा का शिकार हो रही हैं। इस विरोधाभास का एक प्रमुख उदाहरण हरियाणा के झज्जर स्थित अल्पज्ञात स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय है।

खंडहरों में खजाना : आचार्य भगवान देव को बाद में स्वामी ओमानंद सरस्वती के नाम से जाना गया। वर्ष 1960 में उन्होंने हजारों अमूल्य कलाकृतियां जमा करके यह संग्रहालय स्थापित किया था। इसमें से कुछ पांच हजार साल से भी अधिक पुरानी हैं। इस विशाल संग्रह में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के उत्खनन से एकत्रित हड़प्पाकालीन मुहरें, टेराकोटा मूर्तियां, सिक्के, तांबे और कांसे के हथियार, पांडुलिपियां और मूर्तियां शामिल हैं। इनमें राखीगढ़ी से बरामद सामग्री भी शामिल है।

टूटे हुए वादे : झज्जर स्थित संग्रहालय की दुर्दशा दशकों की आधिकारिक उपेक्षा को साफ दर्शाती है। वर्ष 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा नए भवन के निर्माण के लिए 17 लाख रुपये आवंटित किए गए और इसके निदेशक के लिए 50 हजार रुपये मासिक मानदेय स्वीकृत किया गया था। हालांकि मात्र 20 महीनों के बाद मानदेय बंद कर दिया गया था। नतीजतन संस्थान एक बार फिर घटते संसाधनों के बोझ तले दब गया। बाद में केंद्रीय मंत्री बने मनोहर लाल खट्टर ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान संग्रहालय की प्रशंसा की थी। यहां तक कहा कि इसे "हरियाणा का पहला संग्रहालय" माना जाता है। कभी जिसे शोध और अध्ययन का केंद्र माना जाता था, अब वास्तव में यह "एक-व्यक्ति संग्रहालय" बन कर रह गया है। यह कोई अकेला ऐसा मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश के चंदौसी में पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्र संग्रहालय भी पुरावशेषों का एक और निजी तौर पर निर्मित भंडार है। वह भी दुर्दशा का सामना कर रहा है।

हरियाणा में झज्जर स्थित संग्रहालय, जहां धरोहरों के संरक्षण की है आवश्यकता। फाइल

आगे की राह : प्राचीन विरासत के संरक्षण के लिए गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है। सबसे पहले हरियाणा सरकार को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर धन उपलब्ध कराने के लिए आगे आना चाहिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को संस्थागत साझेदार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इन निकायों के पदेन प्रतिनिधित्व के साथ एक संयुक्त प्रबंधन ट्रस्ट बनाने से पेशेवर निगरानी व जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है। तत्काल प्राथमिकताओं में कलाकृतियों का डिजिटल दस्तावेजीकरण, जलवायु-नियंत्रित भंडारण और संग्रह को अकादमिक अनुसंधान के लिए खोलना शामिल होना चाहिए। दूसरा, जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण है। स्थानीय समुदाय, जिन्होंने कभी उदारतापूर्वक योगदान दिया था, उन्हें आउटरीच कार्यक्रमों, सांस्कृतिक उत्सवों और शैक्षिक पहलों के माध्यम से फिर से जोड़ा जाना चाहिए। टिकट वाली प्रदर्शनियां, प्रकाशन और डिजिटल अभिलेखागार जागरूकता बढ़ाते हुए राजस्व उत्पन्न कर सकते हैं। अंत में, कारपोरेट घरानों को सीएसआर के तहत इनके संरक्षण व विकास के लिए आगे आना होगा।

****